(NARP) with assistance from IBRD for strengthening the regional research capabilities of agricultural universities for conducting location specific research in respect of cereals, pulses and oilseeds with particular reference to rainfed farming conditions. According to the existing agreement entered into with the World Bank in respect of this project, assistance is limited to the agricultural universities only and also for food-crops including pulses and oilseeds. Components with regard to mixed farming can be considered for assistance provided they form part of the farming system in the particular zone.

Based on the experience in operating the project during the last one year, a proposal is under consideration of the ICAR to enlarge the scope of NARP to specifically provide assistance for mixed farming and post-harvest technology. Assistance in respect of these two fields is also proposed to be made available to some selected ICAR Research Institutes in addition to agricultural universities.

However, the proposals for enlargement are still in the consideration stage and need to be further discussed and finalised with the Planning Commission and other concerned Departments of the Government of India. Thereafter, the IBRD will be approached to modify the agreement entered into earlier.

टेलीफोन एक्सचेंज, रतलाम

7652. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रतलाम नगर में एक स्वचालित टेलीफोन केन्द्र का निर्माण करने के लिए भूमि खरीदी थी ;

(ख) सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है और इस भूमि का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है ;

(ग) यह भवन कब तक पूरा हो जाएगा और उस पर कितना व्यय होगा,

(घ) रतलाम नगर में अब तक कितने टेलीफोन कनेक्शन हैं; और

(ङ) क्या रतलाम नगर में डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था आरम्भ की जा रही है और यदि हां, तो यह काम कब तक पूरा होने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हां ।

(ख) स्वचालित एक्सचेंज भवन के निर्माण के लिए भूमि आरक्षित कर ली गई है जिसके लिए प्रारूप तैयार किया जा रहा है ।

(ग) अगर समय पर एक्सचेंज उपस्कर उपलब्ध हो गए तो भवन के निर्माण की 1984-85 तक अस्थायी तौर पर योजना बनाई गई है । अब भवन पर लगभग 50 लाख रुपये लागत आने का अनुमान है ।

(घ) 1,133

(ङ) 1985–86 तक स्वाचालित एक्सचेंज के स्थापित किए जाने की अस्थायी तौर पर योजना है ?

झबुआ में कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल

7653. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झबुआ में कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टलों का निर्माण करने की कोई योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ?

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की अनुमानित लागत क्या है ; और